"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 46]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 16 नवम्बर 2018—कार्तिक 25 , शक 1940

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 8 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 4-3/2016/1 (एफ).—राज्य शासन, एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री शरद कुमार गुप्ता, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 12-09-2018 से 14-09-2018 (3 दिन) का पूर्ण वेतन भत्तों सिहत लघुकृत अवकाश का लाभ लेने की स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रीता शांडिल्य, सचिव.

वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक 73/1680/2010/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 21 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची में,-

पैराग्राफ (ङ) में, सरल क्रमांक 14 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :--

"15. भारतीय रेड क्रास सोसायटी"

नया रायपुर, दिनांक 10 जनवरी 2018

क्रमांक 75/1680/2010/स्था./चार.—छत्तीसगढ़ स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1973 (क्र. 43 सन् 1973) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचना क्रमांक एफ. 1 (ए)2/2003/स्था/चार, रायपुर दिनांक 07 दिसम्बर, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

खण्ड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(घ) मुख्यमंत्री सहायता कोष, जिला विधिक प्राधिकरण एवं रोगी कल्याण सिमिति, भारतीय रेड क्रास सोसायटी के लेखों की संपरीक्षा के लिए रुपये 1.00 (रुपये एक मात्र) प्रतिवर्ष के मान से संपरीक्षा शुल्क देय होगी."

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शारदा वर्मा, संयुक्त सचिव.

ऊर्जा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2018

क्रमांक एफ 1-5/2018/13/1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा इफको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंडिका-76 में प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सिद्धार्थ कोमलिसंह परदेशी, सिचव, छत्तीसगढ़ शासन, ऊर्जा विभाग को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष अथवा आगामी आदेश पर्यन्त, जो भी पहले हो, तक इफको छत्तीसगढ़ पॉवर लिमिटेड में डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करता है.

यह आदेश जारी होने की तारीख़ से प्रभावशील रहेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अरविंद कुमार भार्गव, अवर सचिव.

श्रम विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

अटल नगर, रायपुर दिनांक 5 नवम्बर 2018

क्रमांक एफ 6-101/2018/16.—छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16-10-2018 एवं 26-10-2018 में विधानसभा आम निर्वाचन-2018 के सिलसिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हेतु संबंधित जिलों में मतदान की नियत तिथि को स्थानीय अवकाश/सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है. (छायाप्रति संलग्न है).

- 2. भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 78/EPS/2018/993, दिनांक 18-10-2018 द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत, विधानसभा आम निर्वाचन 2018 हेतु नियत मतदान में कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1953 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थाओं के स्थापनाओं में कार्यरत उन श्रमिक/कर्मचारियों के मतदान के दिन अर्थात् दिनांक 12-11-2018 (सोमवार) एवं 20-11-2018 (मंगलवार) को राज्य शासन एतद्द्वारा संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अवकाश घोषित करता है.
- 3. ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश घोषित किये जाने तथा जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा दी जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, **तीरथ प्रसाद लड़िया,** अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दुर्ग, दिनांक 15 नवम्बर 2018

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 12 द्वारा प्राधिकृत	सार्वजनिक प्रयोजन	
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	पाटन	अमलेश्वर प.ह.नं. 05	0.93	कार्यपालन अभियंता, जल प्रबंध क्रमांक-1, रायपुर.	महादेव घाट एनीकट परिक्षेत्र विकास योजना.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन जिला-दुर्ग (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018

क्रमांक 52/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-रायगढ़
 - (ख) तहसील-पुसौर
 - (ग) नगर/ग्राम-बड़े भण्डार
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.313 हेक्टेयर

खसरा नम्बर		रकवा
		(हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	583/2	0.068
	792/2	0.048
	599/7	0.036
	602/2	0.012
	618, 853/2	0.076
	678/4	0.041
	678/5	0.032
योग	7	0.313

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत कठली वितरक एवं बालपुर माईनर नहर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018

क्रमांक 53/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
 - (क) जिला-रायगढ़
 - (ख) तहसील-पुसौर
 - (ग) नगर/ग्राम-छोटे भण्डार
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.145 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	181/2	0.072
2	245/2, 246/2	0.008
	218/5	0.049
	218/4	0.016
योग	4	0.145

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-केलो परियोजना नहर निर्माण के अंतर्गत कठली वितरक नहर हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2018

क्रमांक 54/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूर्च	Ì		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-			115/5	0.073 0.016
(क) जिला-रायगढ़			116/8	0.016
(ख) तहसील-पुसौर (ग) नगर/ग्राम-बादीमाल (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.161 हेक्टेयर		योग	5	0.161
		(2) सार्वज		 ए आवश्यकता है-केलो परियोजना
खसरा नम्बर	रकबा	नहर वि	नेर्माण के अंतर्गत अमल	गिपाली वितरक नहर हेतु.
(1)	(हेक्टेयर में) (2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिका (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.		
116/10	0.024			
79/6, 118/4	0.008	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुस् शम्मी आबिदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-		•
116/9	0.040			कलेक्टर एवं पर्दन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 सितम्बर 2018

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2018-19/4843.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2016-17/1672 रायपुर दिनांक 04-06-2016 द्वारा श्री जोगेन्द्र नायक संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर को कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा, जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

संयुक्त संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय रायपुर के पत्र क्रमांक 2564 दिनांक 18-09-2018 द्वारा श्री जोगेन्द्र नायक संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर के स्थान पर श्री हरवंश सिंह मिरी (डिप्टी कलेक्टर) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर को कृषि उपज मंडी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा श्री जोगेन्द्र नायक संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर के स्थान पर श्री हरवंश सिंह मिरी (डिप्टी कलेक्टर) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) अभनपुर को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति नवापारा जिला-रायपुर का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिजीत सिंह, प्रबंध संचालक.

संचालनालय, स्थानीय निधि संपरीक्षा ब्लाक-1, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

अटल नगर, दिनांक 18 सितम्बर 2018

क्रमांक/एल.एफ.ए./प्रशा./2018/1102.—छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पत्र क्रमांक/612/120/2017/स्था/चार, नया रायपुर दिनांक 10-05-2018 द्वारा प्रदान की गई अनुमित के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित एवं स्थानीय निधि संपरीक्षा विभाग में नियुक्त परिवीक्षाधीन, सहायक संचालक के लिये विभागीय परीक्षा भाग-एक एवं भाग-दो दिनांक 23-07-2018 से 26-07-2018 तक आयोजित की गयी थी, जिसका परीक्षा परिणाम निम्नानुसार है :—

क्रमांक	अनुक्रमांक	सहायक संचालक का नाम	परीक्षा	परिणाम
1.	20181	श्री जितेन्द्र कुमार पैकरा	भाग-एक	उत्तीर्ण
2.	20182	श्रीमती अंजनी राजपूत	भाग-दो	उत्तीर्ण

हस्ता./-संयुक्त संचालक